13. Dr. Satish Kumar, School of International Studies.

14. Dr. K. P. Saxena, School of International Studies.

15. Dr. T. T. Poulose, School of International Studies.

16. Dr. Zafar Imam, School of International Studies.

17. Dr. S. C. Gangal, School of International Studies.

18. Shri B. Vivekanandan, School of Internationl Studies.

19. Dr. P. A. Narasimha Murthy, School of International Studies.

20. Shri Ramesh Dixit, School of International Studies.

21. Dr. (Smt.) Urmila Phadnis, School of International Studies.

22. Shri M. K. Nawaz, Director, Indian Society of International Law.

23. H. E. Mr. Justin Sirwardene High Commissioner of Sri Lanka.

24. Dr. Frank Barnaby, Director, SIPRI (Stockolm). International Institute of Peace Research.

Motorisation of Cycles and Cycle Rickshaws

4371. SHRI B. S. MURTHY : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the present stage of research for motorisation of cycles and cycle rickshaws conducted by the Ministry's Transport Wing; and

(b) the total amount spent on the project so far?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : (a) No research has been conducted by the Ministry of Shipping and Transport in this matter.

(b) Does not arise.

Financial Assistance by Reserve Bank of India to Cooperative Bank of Kerala

4372. SHRIMATI BHARGAVI THANKAPPAN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the amount of financial assistance given by the Reserve Bank of India during 1973-74 to Co-operative Bank of Kerala;

(b) whether this amount was utilised by the Co-operative Bank of Kerala; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) and (b). The credit limits sanctioned by the Reserve Bank of India to the Kerala State Co-operative Bank for 1973-74 for various purposes and utilisation thereof upto February 1974 are as under:—

Purpose	Amount sanctioned (Rs. in lakhs)	Amount utilised (Rs. in lakhs)
1 2	3	4
1. Short-term Agricultural (July to June)	1875.00	1624.60
2. Weavers' Finance (April to March)	135.32	122.94
3. Trading-in-Yarn (April to March)	10.00	10.00
4. Medium term Agricultural (January to December)	73.00*	37.02

*Besides, a sum of Rs. 10 lakhs sanctioned for 1974 on behalf of one Central Cooperative Bank.

(c) Drawals on Medium-term credit limits are comparatively less as the Guarantee executed by the State Government was only for Rs. 42.21 lakhs.

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए योजना मंत्री द्वारा दिए गए सुझाव

4373. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान केन्द्रीय आयोजना मंत्री द्वारा चैम्बर आफ कामर्स में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए दिए गए सुझावों की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो उनका सार क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपाय किये जा रहे है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो पग उठाए गए हैं उनमें ये शामिल हैं :—

(1) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि कर, सिंचाई, उर्वरकों का प्रभावी उपयोग कर, समय पर ऋण देने की व्यवस्था कर और पैदावार में वृद्धि करने हेतु उत्पादकों को प्रोत्साहन मूल्य पेश कर उत्पादन कार्यक्रम में तीव्रता लाना।

(2) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न देना और आयात द्वारा स्टाक में वृद्धि करना।

(3) जमाखोरी निरोधक, तस्करी निरोधक और अन्य विनियामक उपायों को सख्ती से लागू करना।

(4) ऋण-नियंत्रण और अन्य राजकोषीय तथा वित्तीय उपायों आदि को कड़ा करना।

विवरण

कलकत्ता में 23-2-74 की हुई एसोसिएटेड चेम्बर आफ कामर्स एवं इंडस्ट्री आफ इंडिया की बैठक में केन्द्रीय योजना मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए थे :—

(1) खाद्य के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर रखने के लिए यह आवश्यक है कि बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कृषि की पैदावार में वृद्धि की जाए।

(2) शहरों तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या के कमजोर वर्गों को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए सरकार का कृषि जन्य फालतू अनाज पर नियंत्रण होना आवश्यक है।

(3) ग्रामीण जनसंख्या के अब तक उपेक्षित वर्ग को वैज्ञानिक कृषि की परिधि में लाने की दिशा में अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लघु किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को आधुनिक आदानों और ऋण की सुविधाएं सुलभ कर उनकी पैदावार में सुधार लाने के लिए कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

(4) पैदावार में हुई वृद्धि के कारण प्राप्त अतिरिक्त आय का वितरण और समान रूप से किया जाना चाहिए। इसके लिए कृषि में भूमि संस्थागत परिवर्तन लाने होंगे ताकि भारत में आर्थिक प्रगति के आधार को सुदृढ़ किया जा सके।

(5) व्यवहार्य सरकारी वितरण प्रणाली, जोकि मुद्रास्फीति और मूल्य-अस्थिरता का सामना करने के लिए प्रमुख हथियार के रूप में कार्य करेगी, का विकास किया जाना चाहिए। सरकारी वितरण प्रणाली को सफलतापूर्वक चलाने के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करना चाहिये।

(6) सरकारी वितरण प्रणाली मूल्यों में स्थिरता लाने में केवल तभी सफल हो सकती है जब इसे अत्यधिक राज सहायता का भार नहीं वहन करना पड़ता है।